पोलीटेक्निक स्कूल

1280. डा॰ लक्सीनारायण पांडेः क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने पोलीटेक्निक स्कूल अथवा कालेज हैं;

(ख) प्रतिवर्ष इन संस्थाओं में प्रवेश चाहने वाले छ त्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इम प्रकार की आम शिकायत है कि उक्त संस्थाओं से डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार नही मिल रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तकनीकी योग्यताओ वाले व्यक्तियों को तत्काल रोजगार दिलाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में डप-मंत्री (श्री डो॰ पो॰ यादथ) : (क) और (स्र). हमारे देश में इस समय 283 पोली -टेकनिक स्कूल है जिनमे प्रतिवर्ष लगभग 45,000 विद्यार्थियों को प्रवेश देने की क्षमता है। किन्तु इंजीनियरी के स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों में इस समय कैनी हुई बेरोजगारी के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान यह प्रवेश संख्या कम करके 28,000 तक सीमित कर दी गई है।

(ग) और (घ). उद्योगों मे मंदी आने से तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्घारित योजनाओं को स्थगित कर देने के कारण, इंजीनियरी से सम्बद्ध सभी वर्गों के कार्मिकों में पिछले चार-पांच वर्षों से व्यापक बेरोजगारी फैली हुई है। इंजीनियरी सम्बन्धी कार्मिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न करने हेनु केन्द्रीय सरकार ने 1968 में अनेक उपाय शुरू किये थे। इन उपायों तथा अब तक हुई प्रगति के विषय में एक विस्तत विवरण तारांकित प्ररून संख्या 46 के उत्तर के साय 31 मार्च 1971 को सभा-पटल पर रखा जा चुका है।

संस्कृत का प्रवार और विकास

1281.डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेः क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान संस्कृत के प्रचार और विकास पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) किस माघ्यम से यह राशि व्यय की जाती है ;

(ग) क्या संस्कृत के प्रचार और विकास के लिये सरकार को सुझाव देने के लिए कोई विशेष समिति गठित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यो के नाम क्या हैं ?

शिक्ता और समाज कल्पाण मंत्रालय में उप-मंत्री (भी डो॰ पी॰ यादव): (क) 49.88 लाख रुपये।

(ख) राज्य सरकारें, स्वायत्तज्ञासी संगठन, स्वैच्छिक संस्कृत संगठन/संस्था और व्यक्ति ।

(ग) केन्द्रीय संस्कृत परिषद की स्थापना (भूतपूर्व केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के स्थान पर) जनवरी, 1970 में की गई थी, जो संस्कृत प्रचार और विकास से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देती हैं।

(घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया हैं। [ग्रंबालय में रखा गया। बेलिये संख्या LT-315/71]

भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी विद्यार्थी

1282. डा० सक्सी नारायन वांडे : क्या सिक्सा और समाज सल्याज मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे कि :

53

(क) उन भारतीय शौक्षिक सस्याओं के नाम क्या है तया वे कहा स्थित हे जहा इस समय विदेशी थिद्य थीं जिक्षा पा रहे हे ;

(म्व) उन बिद्यार्थियों की सल्या किन्ती है तयावे किन किन देशाके है; और

(ग) उन पर सरकार प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च करनी है?

शिक्षा और समाज कल्पाण मत्रालय में उप-मत्री (श्री डी॰ पी॰ यादव) : (क) और (ख). विश्वविद्यालयों में प्राप्त हुई अद्यतन उपलब्ध सूचना जो 1968-69 से सम्बन्धित है, विव-रणों में दी गई है, जो सभा पटल पर रख दिये गये है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सख्या LT-316/71]

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

Appointment of Managing Director of M/S. Indian Oxygen Ltd.

1283. SIIRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: Will the Minister of COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether M/s. Indian Oxygen Limited have, in their last annual meeting approved the appointment of their Managing Director on remunerations which violates the statutory limit fixed lately by Government;

(b) whether the same has been approved by Government ; and

(c) if so, the action being taken by Government to bring the remuneration of the said managing director down within the statutory limits?

THE MINISTER OF COMPANY AF-FAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY): (a) to (c). Mr. Keith Hartley was Assistant Managing Director of the Company from Ist April, 1963 and was promoted as Joint Managing Director with effect from Ist September, 1969 on a salary of Rs. 8000/- p.m., overseas allowance of Rs. 1500/- p.m. and perquisites. Recently the company sought approval to his appointment as Managing Director with effect from Ist April, 1971 on the same salary of Rs. 8000/- with increased foreign allowance of Rs. 2500/- pm. in addition to commission at 1% of the net profits not exceeding Rs. 45,000/- per annum and perquisites. Although the proposed salary was in excess of the administrative ceiling of Rs. 7,500/-, it was approved in view of the fact that Mr. Hartley was alleady drawing the same previously as the Joint Managing Director and this came within the recognized exceptions. His total remuneration by way of salary and commission was however made subject to the administrative ceiling of Rs. 1.35 lacs per annum and no increase in Overseas Allowance was allowed. This remuneration was subject to the approval of the company at its general meeting as required under Section 309 (1).

The Thirty Sixth Annual General Meeting of the Company was scheduled to be held m February, 1971. It is not yet known if the said meeting was held and whether the proposed remuneration was approved or not.

Abolition of Reservation of seats for Scheduled Castes in Assemblies and Parliament

1284. SHRI MUHAMMAD SHERIFF: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have considered the abolition of reservation of seats for Scheduled Castes in the Assemblies and Parliament; and

(b) if so, the decision arrived at ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. S. RAMA-SWAMY): (a) and (b). The matter was considered at the time of the passing of the Constitution (Twentythird Amendment) Act, 1969, which has extended the period of such reservations up to the 25th January, 1980.